09

अध्याय

सेवा क्षेत्र

भारत के सकल मूल्य वर्धन में 55.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख संचालक बना हुआ है और 2017-18 में सकल मूल्यवर्धन वृद्धि में लगभग 72.5 प्रतिशत का योगदान रहा। यद्यपि इस क्षेत्र की वृद्धि 2017-18 में 8.3 प्रतिशत होने का अनुमान है, 2017-18 के पूर्वार्ध में सेवा निर्यात और निवल सेवाओं में वृद्धि क्रमशः 16.2 प्रतिशत और 14.6 प्रतिशत के सुदृढ़ स्तर पर रही। सरकार ने विभिन्न सेवाओं में बहुत सी पहलें की हैं जिनमें डिजीटलीकरण, ई-वीसा, संभारतंत्र को अवसंरचना का दर्जा देना, स्टार्ट-अप-इंडिया, आवास क्षेत्र के लिए स्कीमें आदि शामिल हैं, जिनसे इस क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं

9.1 संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के आंकड़ों के अनुसार, विश्व के 15 बड़े देशों में समग्र जीडीपी के अनुसार भारत का स्थान 2006 में 14वें स्थान से सुधरकर 2016 में 7वें पर आ गया, इन शीर्ष 15 देशों में, चीन ने (9.8 पीपी) 2006-16 के दौरान सकल मूल्यवर्धन में सेवाओं की हिस्सेदारी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, इसके बाद भारत (7.1 पीपी) और स्पेन (7.0 पीपी) का स्थान आता है। वर्ष 2016 में, सेवा जीवीए वृद्धि दर (स्थिर कीमतों पर) भारत में 7.8 प्रतिशत पर सबसे अधिक थी, इसके बाद चीन की 7.4 प्रतिशत पर थी। आईएलओ अनुमानों के अनुसार 2016 में शीर्ष 15 देशों में, भारत और चीन को छोड़कर अधिकांश में कुल रोजगार के दो तिहाई से भी अधिक का योगदान सेवा क्षेत्र का था, भारत का हिस्सा 30.6 प्रतिशत पर सबसे कम था। जबकि 2006 से 2016 की अवधि के दौरान चीन के सेवा रोजगार के हिस्से में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी (10.2 पीपी) भारत में यह वृद्धि केवल 5.2 पीपी थी (चित्र 1)।

चित्र 1: 2006-16 के दौरान रोजगार और जीवीए में सेवाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि

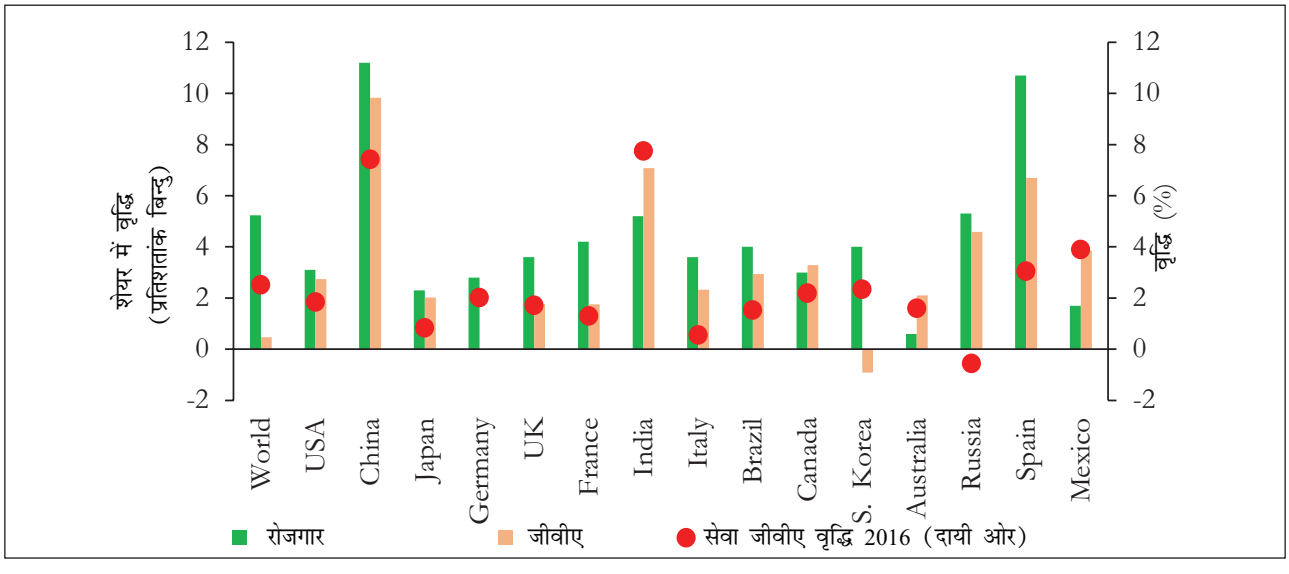

स्रोत: जीवीए के लिए यूएन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के आंकड़ों और रोजगार के लिए विश्व बैंक के आंकड़ों से संगणित।

9.2 सेवा निर्यात वृद्धि, विश्व और भारत दोनों के लिए, 2009 से 6 वर्ष के अंतराल के बाद 2015 में गिरकर ऋणात्मक हो गई थी, 2016 में घनात्मक स्थिति में आ गई। विश्व व्यापार संगठन के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, 2017 की पहली छमाही के लिए विश्व के लिए सेवा निर्यात वृद्धि 4.3 प्रतिशत (पहली और दूसरी तिमाही का औसत) और भारत के लिए 9.9 प्रतिशत पर थी, फिर भी रूस द्वारा 18.4 प्रतिशत सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। चीन की वृद्धि 0.2 प्रतिशत थी। (चित्र 2)

9.3 व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा प्रकाशित विश्व निवेश रिपोर्ट 2017 के अनुसार, 2015 में विदेशी निवेश में तेजी आने के कारण वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह 2016 में कमजोर आर्थिक विकास की दशा में 2 प्रतिशत घटकर 1.75 ट्रिलियन अमरीकी डालर पर आ गया। 2017 में वैश्विक एफडीआई प्रवाह के लगभग 5 प्रतिशत बढ़ने का पूर्वानुमान है। 2015 में, सेवा क्षेत्र का योगदान वैश्विक एफडीआई स्टॉक का दो तिहाई था, यद्यपि इसका एक बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र और विनिर्माण बहुराष्ट्रीय उद्यमों के संबद्ध शाखाओं से संबंधित है जो सेवा जैसे क्रियाकलाप करते हैं और सामान्य श्रेणी के रूप में सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। कुल घोषित ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के कुल मूल्य में सेवाओं का हिस्सा पिछले वर्ष 54.1 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 58.2 प्रतिशत हो गया।

भारत का सेवा क्षेत्र

सेवाओं का सकल मूल्यवर्धन

9.4 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी राष्ट्रीय आय 2017-18 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान सेवा क्षेत्र में वृद्धि (जीवीए स्थिर (2011-12) कीमतों पर) 8.3 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो वर्ष 2016-17 में हुई 7.7 प्रतिशत से अधिक है। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण श्रेणी से संबंधित सेवाओं में वर्ष 2017-18 के दौरान 8.7 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है जबकि 2016-17 में 7.8 प्रतिशत में की वृद्धि हुई थी। वित्तीय, वर्ष के दौरान स्थावर संपदा और व्यवसायिक सेवाओं की श्रेणी में वृद्धि दर 2016-17 के 5.7 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 2017-18 में 7.3 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। 'लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं' श्रेणी में 2015-16 के 6.9 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 के दौरान 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के चलते सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली मजदूरी और वेतन के अधिक भुगतान के कारण रहा। वर्ष 2017-18 में वृद्धि में 9.3 प्रतिशत की कमी होने की संभावना है जो वर्ष 2016-17 के कुछ आधार पर है (सारणी 1)।

चित्र 2: वर्षानुवर्ष वाणिज्यिक सेवा निर्यात वृद्धि (प्रतिशत)

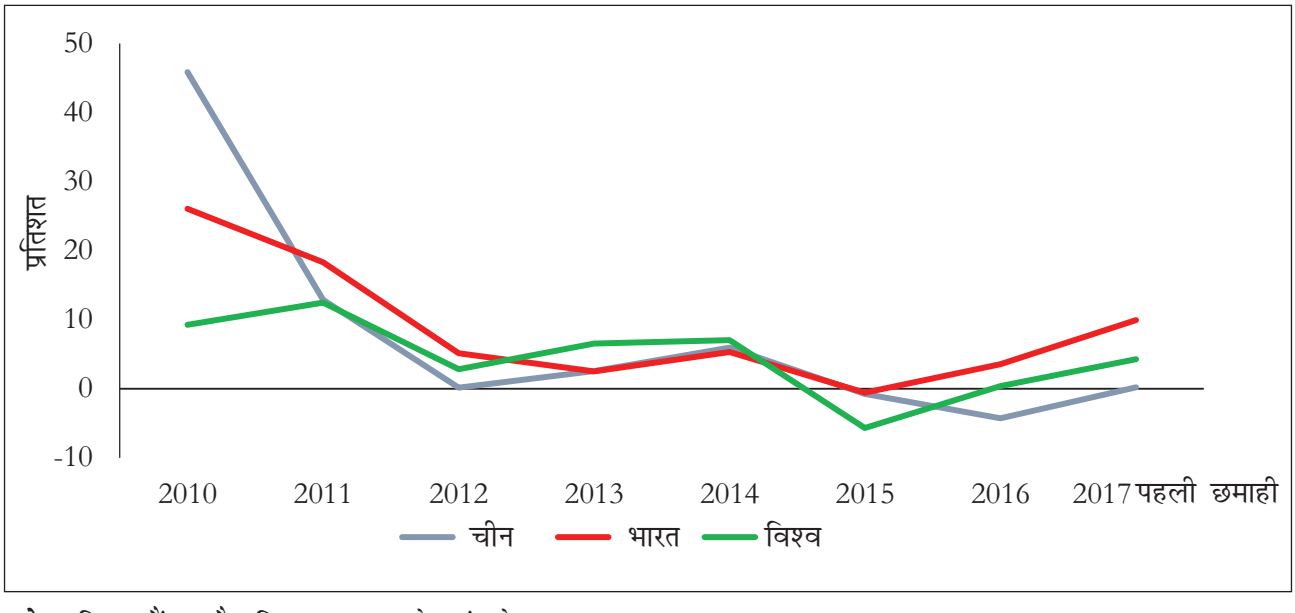

स्रोत: विश्व बैंक और विश्व व्यापार के आंकड़े

टिप्पणी: एच 1 = विश्व के लिए पहली तिमाही और दूसरी तिमाही का औसत।

सारणी 1: भारत के सेवा क्षेत्र का हिस्सा और विकास (आधार मूल्य पर जीवीए)

	शेयर (प्रतिशत)	वृद्धि (प्रतिशत)		
	2015-16	2015-16	2016-17@	2017-18#
सभी सेवाएं	**52.9**	**9.7**	**7.7**	**8.3**
व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां	11.4	11.2	7.8*	8.7*
व्यापार और मरम्मत सेवाएं	10.4	10.9	--	--
होटल और रेस्तरां	1.0	14.4	--	--
परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं	7.0	9.3	--	--
रेलवे	0.8	7.0	--	--
सड़क परिवहन	3.2	6.7	--	--
हवाई परिवहन	0.2	16.8	--	--
वित्तीय सेवाएं	5.8	6.8	5.7^	7.3^
स्थावर सम्पदा, रिहायशों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं	15.3	12.5	--	--
लोक प्रशासन और रक्षा एवं अन्य निर्माण	13.4	6.9	11.3	9.4
कुल सेवा (निर्माण सहित)	8.1	5.0	1.7	3.6
कुल जीवीए/आधार कीमतों पर	**61.0**	**9.1**	**6.9**	**7.7**
जीडीपी बाजार कीमतें (स्थिर कीमतों पर) वर्षानुवर्ष	**100.0**	**7.9**	**6.6**	**6.1**
		8.0	**7.1**	**6.5**

स्रोत: **केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों से संगणित**
टिप्पणी: **अंश वर्तमान कीमतों पर और वृद्धि स्थिर 2011-12 कीमतों पर हैं,**
@2016-17 के लिए अनंतिम अनुमान; #पहले अग्रिम अनुमान;
***इसमें परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से जुड़ी सेवाएं भी शामिल हैं;**
^इसमें स्थावर सम्पदा, रिहायशों का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं।

सेवाओं की राज्य-वार तुलना

9.5 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से, जिनके लिए केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा नई आधार 2011-12 श्रृंखला हेतु आंकड़े जारी किए गए हैं, सेवा क्षेत्र का 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्चस्व है जिसका, सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधे से भी अधिक योगदान है। अधिकांश राज्यों में मुख्य सेवाएं व्यापार, होटल और रेस्तरां हैं, इसके बाद स्थावर सम्पदा, रिहायशी मकानों का स्वामित्व और कारोबार सेवाओं का स्थान आता है। तथापि, सेवा जीएसवीए की हिस्सेदारी और वृद्धि के संदर्भ में व्यापक भिन्नता भी है। 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से, जिनके लिए 2016-17 के आंकड़े उपलब्ध हैं (या अद्यतन वर्ष जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं), सेवा जीएसवीए हिस्सेदारी के संदर्भ में दिल्ली और चंडीगढ़ शीर्ष पर हैं, जिनकी हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है जबकि सिक्किम 31.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ निचले पायदान पर है। सेवा जीएसवीए वृद्धि के अर्थ में बिहार शीर्ष पर है और उत्तर प्रदेश निचले पायदान पर 2016-17 में क्रमशः 14.5 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत वृद्धि दरें रही हैं। (चित्र 3)

चित्र 3: राज्यों में सेवाओं की हिस्सेदारी और वृद्धि 2016-17)

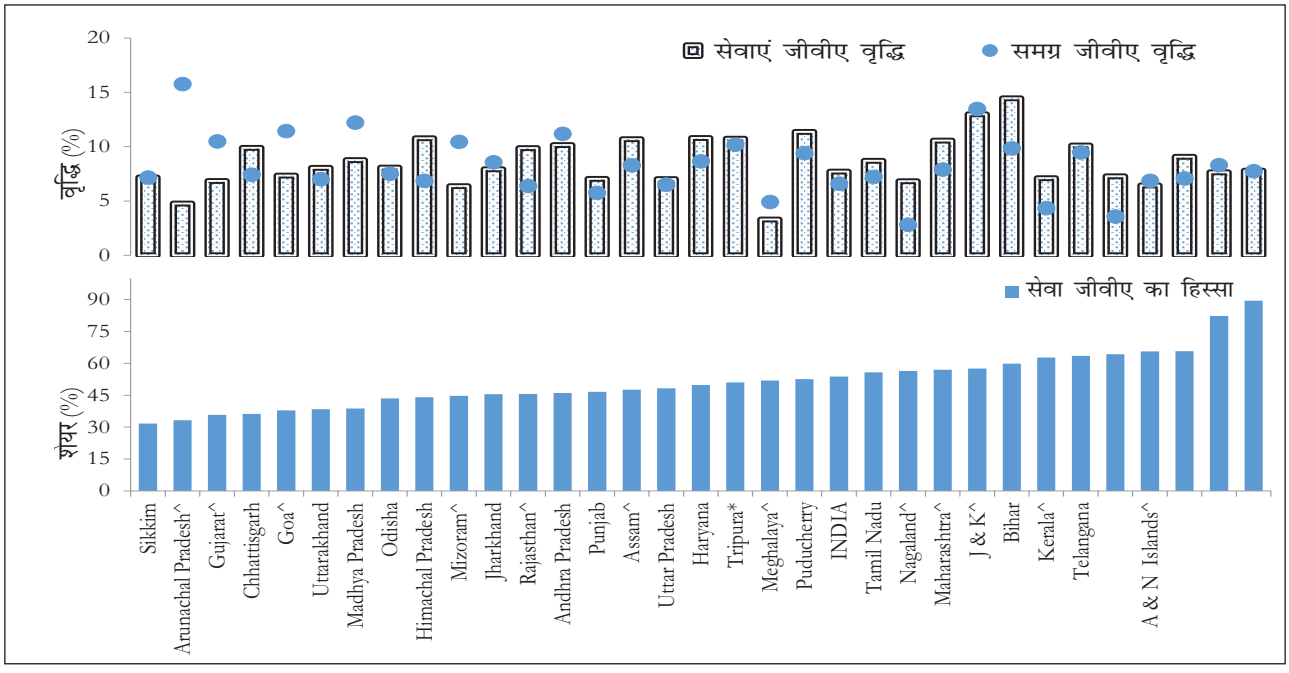

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों से संगणित।

टिप्पणी: *2014-15, ^2015-16, हिस्सेदारी वर्तमान कीमतों और वृद्धि स्थिर कीमतों (2011-12) पर।

भारत के सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

9.6 यद्यपि सेवाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वर्गीकरण में अस्पष्टता है, यह शीर्ष 10 सेवा क्षेत्रों की संयुक्त एफडीआई हिस्सेदारी है जैसाकि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की सेवा क्षेत्र की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाएं; तथा दूरसंचार; व्यापार, कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर; निर्माण, होटल, पर्यटन, अस्पताल और नैदानिक केन्द्र, परामर्शी सेवाएं, समुद्री, परिवहन और सूचना तथा प्रसारण जिन्हें सेवा एफडीआई के सर्वोत्तम अनुमान के रूप में लिया जा सकता है।, तथापि इनमें कुछ गैर सेवा तत्व शामिल हो सकते हैं। इन सेवाओं की हिस्सेदारी अप्रैल 2000-अक्तूबर 2017 की अवधि के दौरान संचयी एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का 56.6 प्रतिशत है और 2017-18 (अप्रैल-अक्तूबर के दौरान एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का 65.8 प्रतिशत है। यदि अन्य 5 सेवाओं की या सेवा से संबंधित क्षेत्रों जैसे खुदरा व्यापार, कृषि सेवाएं, शिक्षा, पुस्तक मुद्रण और हवाई परिवहन के हिस्से शामिल किए जाएं तब सेवा क्षेत्र के लिए एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह की कुल हिस्सेदारी उपर्युक्त दो अवधियों के लिए बढ़कर क्रमश 58.5 प्रतिशत तथा 69.6 प्रतिशत हो जाएगी। वर्ष 2016-17 में सेवा क्षेत्र (निर्माण सहित शीर्ष 10 क्षेत्रों) में एफडीआई अन्तर्वाहों में 0.9 प्रतिशत की गिरावट आई ये 26.4 अमरीकी डालर बिलियन के रहे हालांकि एफडीआई इक्विटी अन्तर्वाहों में समग्र रूप से 8.7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। तथापि वर्ष 2017-18 के दौरान (अप्रैल-अक्तूबर) कुल एफडीआई इक्विटी अन्तर्वाहों में 0.8 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 15.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मुख्यत: दो क्षेत्रों अर्थात दूरसंचार और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अपेक्षाकृत अधिक एफडीआई के कारण थी (सारणी-2)।

9.7 पिछले तीन वर्षों में, सरकार ने कई सुधार किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत निवेश के लिए उत्तरोत्तर रूप से आकर्षक स्थान बना रहे। जिसमें राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार नीति (आइपीआर) की घोषणा, वस्तु एवं सेवा कर का क्रियान्वयन, व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए किए गए सुधार जिसके परिणामस्वरूप भारत का स्थान 30वें रैंक पर पहुंच गया, शामिल है। इन सुधारों के स्तर का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इस अवधि के दौरान, सेवा कार्यकलापों को भी शामिल करते हुए 25 क्षेत्रों और एफडीआई नीति के 100 क्षेत्रों को कवर करते हुए सुधार किए गए हैं। निर्माण विकास, प्रसारण, खुदरा व्यापार, हवाई यातायात, बीमा और पेंशन जैसे क्षेत्रों से संबंधित एफडीआई नीति प्रावधानों में व्यापक सुधार किए गए थे। वर्तमान में, 90 प्रतिशत से भी अधिक एफडीआई अन्तर्वाह स्वत: मार्ग के जरिए आते हैं।

सारणी 2. सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

क्र.सं.	क्षेत्र	मूल्य (बिलियन यूएस $ में)		कुल का प्रतिशत (%) हिस्सा	वृद्धि दर %	
		2016-17	2017-18 (अप्रैल-अक्तूबर)	अप्रैल 2000 - अक्तूबर 2017	2016-17	2017-18 (अप्रैल-अक्तूबर)
1	सेवा क्षेत्र*	8.7	3.4	17.6	26.0	-45.8
2	निर्माण#	2.0	1.4	9.9	-57.5	22.0
3	दूरसंचार	5.6	6.1	8.4	320.1	115.9
4	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर	3.7	3.3	7.8	-38.2	116.0
5	कारोबार	2.3	1.6	4.4	-39.2	-1.2
6	होटल और पर्यटन	0.9	0.6	3.0	-31.3	-4.1
7	सूचना और प्रसारण	1.5	0.5	2.0	50.3	-48.9
8	अस्पताल और निदान केंद्र	0.7	0.6	1.4	0.7	6.9
9	परामर्शी सेवाएं	0.3	0.4	1.1	-49.5	137.6
10	समुद्री यातायात	0.7	0.6	0.9	71.2	71.1
	शीर्ष 10 सेवा श्रेणियां (1-10)	**26.4**	**18.4**	**56.6**	**-0.9**	**15.0**
	शीर्ष 15 सेवाएं	**27.2**	**19.5**	**58.5**	**-1.7**	**17.5**
	कुल एफडीआई	**43.5**	**28.0**	**100.0**	**8.7**	**0.8**

स्रोत: **औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) के आंकड़ों पर आधारित।**

टिप्पणी: ***वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, आरएंडडी, कोरियर, प्रौद्योगिकी परीक्षण और विश्लेषण;**

#अवसंरचना कार्यकलापों और टाउनशिप, आवासीय, तैयार अवसंरचना तथा निर्माण-विकास परियोजनाओं को मिलाकर।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा एफडीआई आवेदनों की आनलाइन प्रक्रिया इ-फाइलिंग के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद सरकार ने वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में एफआईपीबी को समाप्त करने की घोषणा की थी। हाल ही में 10 जनवरी 2018 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एफडीआई नीति में संशोधनों को अनुमोदित किया जिनके जरिए एकल ब्रांड खुदरा व्यापार के लिए स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। विदेशी एयरलाइनों को भी एयर इंडिया में 49 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी गई है।

भारत का सेवा व्यापार

9.8 भारत विश्वभर में वर्ष 2016 (डब्ल्यूटीओ 2017) में 3.4 प्रतिशत के हिस्से के साथ वाणिज्यिक सेवाओं का आठवां सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है जो भारत के पण्य निर्यात के 1.7 प्रतिशत हिस्से से दोगुना है। इसके अलावा भारत के निर्यातों में सेवा क्षेत्र की बढ़ती महत्ता को दर्शाते हुए सेवा निर्यात और पण्य निर्यात का अनुपात 2000-01 में 35.8 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 58.2 प्रतिशत हो गया है जबकि भारत के सेवा निर्यातों ने 2006-07 से 2016-17 के दौरान 8.3 प्रतिशत सीएजीआर दर्ज की थी, 2015-16 में इसने (-) 2.4 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की थी। 2016-17 में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ सेवा क्षेत्र की निर्यात वृद्धि सकारात्मक वृद्धि में बदल गई। यात्रा और सॉफ्टवेयर सेवाओं जैसे कतिपय प्रमुख क्षेत्रों में कारोबार के साथ अप्रैल-सितम्बर 2017-18 के दौरान सेवा निर्यात ने 16.2 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की थी (सारणी 3)। विदेशी पर्यटकों के आगमन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ यात्रा प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2017-18 की पहली छमाही में 27.7 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि देखी गई थी। पारम्परिक सेवाओं के कीमत दबावों और चुनौतीपूर्ण कारोबार के वैश्विक माहौल का सामना करने के बावजूद घरेलू साफ्टवेयर कम्पनियों, सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातों में 2.3 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जो पिछली अवधि की तुलना में मामूली सा सुधार है।

9.9 अप्रैल-सितम्बर 2017-18 में भारत के सेवा निर्या. तों ने 17.4 प्रतिशत की वृद्धि को प्राप्त कर लिया चूंकि यातायात क्षेत्र के भुगतानों में 15.0 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हुई। अन्य प्रमुख सेवा आयातों में यात्रा में 12 प्रतिशत तक और व्यवसाय सेवाओं में 11.3 प्रतिशत तक वृद्धि हुई (सारणी 3)। व्यवसाय सेवा भुगतानों में वृद्धि मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास सेवाओं, व्यवसायिक और प्रबंधन संबंधी परामर्शी सेवाओं और तकनीकी व्यापार संबंधी तथा अन्य व्यावसायिक सेवाओं के आयात के लिए उच्चतर भुगतानों के कारण हुई। हालांकि साफ्टवेयर सेवा आयातों का हिस्सा केवल 4.3 प्रतिशत था, इसकी वृद्धि लगभग 47.6 प्रतिशत के आस-पास थी।

9.10 2015-16 और 2016-17 में आयातों की तुलना में सेवा निर्यातों में कम वृद्धि से निवल सेवा प्राप्तियों में गिरावट आई। अप्रैल-सितम्बर 2017-18 के दौरान निवल सेवा प्राप्तियों में 14.6 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हुई। सेवा क्षेत्र में निवल अधिशेष ने 2017-18 के पूर्वार्द्ध में भारत के लगभग 49 प्रतिशत पण्य घाटे को वित्तपोषित किया था और चालू खाता घाटे के आघात को झेलने में मदद की थी।

9.11 सेवा निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015-2020 की अपनी मध्यवार्षिक समीक्षा में भारतीय सेवा निर्यात स्कीम (एसइआईएस) के अन्तर्गत 1,140 करोड़ रु. के अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन जिससे होटल एवं रेस्त्रां, हॉस्पीटल, शैक्षणिक सेवाओं आदि सहित सेवा निर्यातों में मदद मिल सकती है, के प्रोत्साहनों में 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। यद्यपि वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक व्यापार परिमाण में 2018 में तेजी आने का पूर्वानुमान है, बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितता, संरक्षणवाद और अधिक कड़े प्रवासी नियम भारत के सेवा निर्यातों की रूप रेखा में प्रमुख कारक बनेंगीं।

प्रमुख सेवाएं: समग्र निष्पादन

9.12 सीएमआईई आंकड़ों (सारणी 5) के साथ वर्ष 2016-17 (सारणी 4) भारत में विभिन्न सेवाओं के कतिपय उपलब्ध संकेतक पर्यटन, विमानन और दूरसंचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय अच्छे निष्पादन को दर्शाते हैं। वर्ष 2017-18 के लिए उपलब्ध सीमित आंकड़े भी इन तीन क्षेत्रों में अच्छे निष्पादन की ओर संकेत करते है।

सारणी 3: भारत की मुख्य सेवाओं का व्यापार निष्पादन

	मूल्य (बिलियन यूएस $ में)	शेयर (%)	वृद्धि (%)			
	2016-17	2016-17	2015-16	2016-17	2016-17 H1	2017-18 H1
सेवा निर्यात	**163.1**	**100.0**	**-2.4**	**5.7**	**4.2**	**16.2**
यात्रा	23.2	14.2	4.6	9.3	7.6	27.7
यातायात	15.9	9.7	-19.9	13.2	9.6	6.9
विविध	121.2	74.3	-0.9	4.1	3.1	15.6
सॉफ्टवेयर सेवाएं	73.7	45.2	1.4	-0.7	0.0	2.3
व्यवसाय सेवाएं	32.9	20.2	2.0	13.6	8.4	7.6
वित्तीय सेवाएं	5.1	3.1	-12.7	3.1	-4.1	-13.4
सेवा आयात	**95.7**	**100.0**	**3.7**	**13.0**	**16.5**	**17.4**
यात्रा	16.4	17.2	-3.4	11.1	15.7	12.0
यातायात	14.1	14.8	-6.8	-6.3	-10.0	15.0
विविध	63.0	65.9	9.8	19.5	26.5	19.3
सॉफ्टवेयर सेवाएं	3.6	3.7	-0.3	32.9	25.9	47.6
व्यवसाय सेवाएं	32.3	33.7	12.5	3.7	8.3	11.3
वित्तीय सेवाएं	5.9	6.1	-12.4	86.7	69.3	-0.2
निवल सेवा निर्यात	**67.5**	**100.0**	**-9.0**	**-3.2**	**-10.0**	**14.6**

स्रोत: आरबीआई के भुगतान शेष (बीओपी) डाटा (बीपीएम-5) पर आधारित।

9.13 व्यापार और जहाजरानी सेवा की मजबूती दर्शाने वाली माल भाड़ा सूची और अच्छे निष्पादन का एक मुख्य सूचक दि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 20 मई, 2008 को 11,793 के शीर्ष से 8 दिसंबर, 2008 को गिरकर 663 के निम्न स्तर पर आ गया था। और यह 11 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार 290 पर खतरे की स्थिति में रहा, और इसमें तबसे कुछ सुधार हुआ है और यह 17 जनवरी, 2018 को 1,164 पर था (चित्र 4)।

सारणी 4: भारत के सेवा क्षेत्र का निष्पादन: कुछ संकेतक

क्षेत्र	संकेतक	यूनिट	अवधि			
			2009-10	2015-16	2016-17	2017-18
आईटी- बीपीएम*	आईटी-बीपीएम सेवा आगम	यूएस $ बिलियन	64.0	129.4	139.9	150-152[P]
	निर्यात	यूएस $ बिलियन	49.7	107.8	116.1	124-125[P]
	घरेलू	यूएस $ बिलियन	14.3	21.6	23.8	26-26.5[P]
विमानन*	एयरलाइन यात्री (कुल)	मिलियन	77.4	135.0	158.4	(76.1)86.7[#]
	घरेलू	मिलियन	45.3	85.2	103.7	(49.5)57.5[#]
	अंतरराष्ट्रीय	मिलियन	32.1	49.8	54.7	(26.6)29.2[#]
दूरसंचार	दूरसंचार कनेक्शन	बिलियन	0.6	1.0	1.2	(1.1)1.2
	(वायरलाइन और वायरलैस)[ख]	मिलियन	5.2	8.0	8.8	10.2
	विदेशी पर्यटक आगमन[क]	यूएस $ बिलियन	11.1	21.1	22.9	27.7
पर्यटन	पर्यटन से विदेशी	मिलियन	9.6	10.9	11.6	12.7[@]
	मुद्रा आय[क]	यूएस $ बिलियन	998	1273	1316	1374[@]
जहारानी	भारतीय जहाजरानी का सकल टन भार[ख]	मिलियन जीटी	850.0	1071.9	1133.1	574.7[#]
	जहाजों की संख्या[ख]	संख्या				
पत्तन	पत्तन यायायात	मिलियन टन				

स्रोत: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), पर्यटन मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, एनएएसएससीओएम से संकलित।

टिप्पणी: [क]कलैंडर वर्ष, उदाहरणार्थ 2009-10 के लिए 2009; [ख]आगामी वित्त वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार; @30 जून, 2017 की स्थिति के अनुसार डाटा, #डाटा अप्रैल-सितम्बर 2017 के लिए है; ~डाटा अक्तूबर 2017 की स्थिति के अनुसार है; ^डाटा जनवरी से नवम्बर 2017 के लिए है जीटी=सकल टनभार; एमटी=मैट्रिक टन हार्डवेयर को छोड़कर; 2017-18 के लिए पूर्वानुमानित दायरा। *घरेलू यात्रियों का आवागमन केवल अनुसूचित घरेलू सेवाओं पर अनुसूचित भारतीय वाहकों द्वारा हुआ और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का आवागमन भारतीय राज्य-क्षेत्र में और से अनुसूचित भारतीय एवं विदेशी वाहकों द्वारा हुआ; कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की इसी अवधि के है।

चित्र 4: बाल्टिक ड्राई इंडेक्स

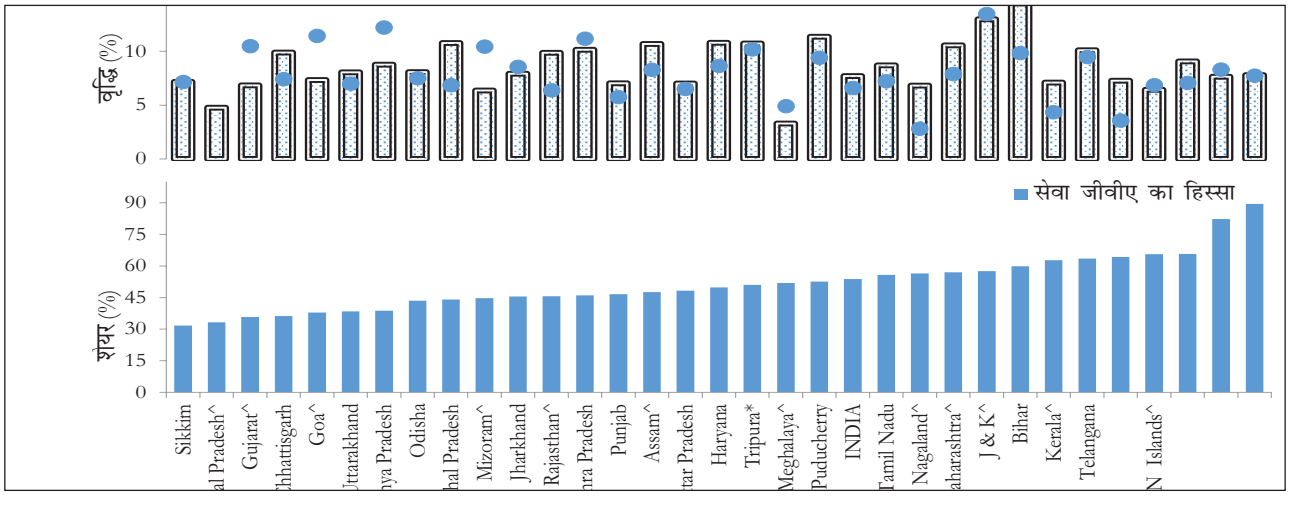

स्रोत: https://in.investing.com/indices/baltic-dry-historical-data

सारणी 5: चुनिंदा सेवाओं की निवल बिक्री में वृद्धि: कंपनी आधारित डाटा निवल बिक्री

सेवा	निवल बिक्री							
	2015-16	2016-17	2016-17				2017-18	
			ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2
यातायात संभारतंत्र	1.0	7.3	4.9	6.7	9.8	7.7	6.6	4.3
जहाजरानी	-1.6	-18.7	-25.2	-29.2	-12.8	-4.7	5.1	4.4
विमानन	6.7	9.1	6.0	14.1	9.5	34.6	18.7	12.6
खुदरा	23.0	19.5	29.7	29.5	0.8	23.7	24.4	9.6
कारोबार	15.4	12.8	12.1	14.4	13.6	11.2	10.8	10.5
स्वास्थ्य सेवाएं	8.1	2.7	2.0	4.3	3.9	0.8	4.8	-2.6
होटल एवं रेस्तंरा	17.8	9.5	18.8	8.2	7.1	5.2	5.2	0.7
आईटीईएस	11.2	7.2	10.7	6.8	7.3	4.5	3.0	4.7
सॉफ्टवेयर	7.6	-1.9	4.9	-6.5	-3.5	-1.9	7.4	-3.6
निर्माण एवं रियल एस्टेट								

स्रोत: एक्जिम बैंक रिसर्च (सीएमआईई से प्राप्त डाटा)

टिप्पणी: वार्षिक आंकड़े, सकल बिक्री को संदर्भित करते हैं।

9.14 पिछली कुछ तिमाहियों में सेवा क्षेत्र की फर्मों के बिक्री के परिणामों का विश्लेषन दर्शाता है कि केवल वे क्षेत्र जो दबाव का संकेत दे रहे है वे क्षेत्र निर्माण और रीयल एस्टेट है। 2017-18 की पहली दो तिमाहियों में दूसरी तिमाही में होटल एवं रेस्तंरा और निर्माण एवं रीयल एस्टेट को छोड़कर सभी क्षेत्र अच्छा निष्पादन कर रहे हैं।

प्रमुख सेवाएं: क्षेत्रवार निष्पादन और कुछ हालिया नीतियां

9.15 इस खंड में भारत के लिए जरूरी कुछ सेवाओं को जीडीपी/जीवीए, रोजगार, निर्यात और भविष्य की संभावनाओं की दृष्टि से उनके महत्व के आधार पर वर्णित किया गया है। दूसरे अध्यायों में उल्लिखित कुछ जरूरी सेवाएं दोहराव से बचने के लिए इसमें शामिल नहीं की गई हैं।

पर्यटन

9.16 संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन (दिसम्बर, 2017 प्रकाशन) के नवीनतम वैश्विक पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार, 2016 में अन्तरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन कुल मिलाकर 1.2 बिलियन तक पहुंच गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 46 मिलियन अधिक था, हालांकि 3.9 प्रतिशत की यह वृद्धि दर 2015 (4.6 प्रतिशत) की तुलना में मामूली सी कम थी। भारत में, 2016 में 8.8 मिलियन विदेशी पर्यटक आए (9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई) और 22.9 बिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा अर्जन (8.8 प्रतिशत की वृद्धि) के साथ पर्यटन क्षेत्र अच्छा निष्पादन कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, 2017 के दौरान 15.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10.2 मिलियन, विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ जबकि 2016 की तुलना में 20.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 27.7 बिलियन, अमरीकी डालर विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी (चित्र 5)।

चित्र 5: विदेशी पर्यटक आगन्तुकों, विदेशी मुद्रा राजस्व और देशी पर्यटकों में वृद्धि

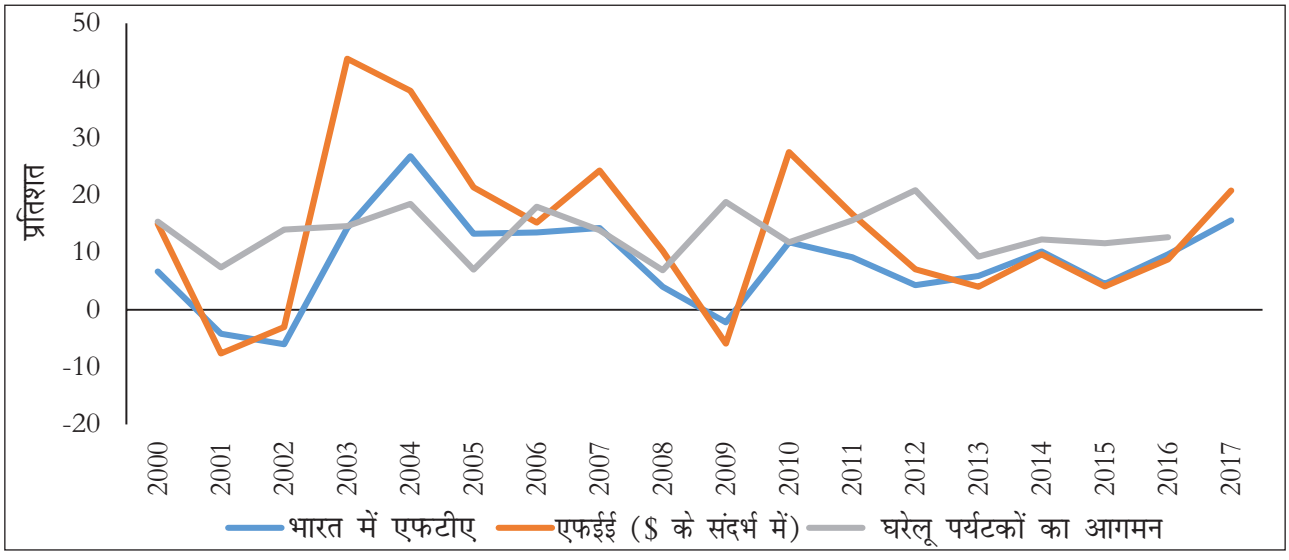

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित

9.17 हाल के वर्षों में विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है भारत से बाहर जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 7.3% की दर से बढ़ रही है, और यह 2015 में 20.4 मिलियन से बढ़कर 2016 में 21.9 मिलियन थी। यह भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या से दो गुनी है। 2016 के दौरान देशी पर्यटकों की संख्या में 12.7% की दर से वृद्धि हुई और यह 2015 में 1,432 मिलियन से बढ़कर 2016 में, 1,614 मिलियन थी। 2016 में देशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले 5 शीर्ष राज्यों में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक थे, जिन्होंने 2016 के दौरान कुल देशी पर्यटकों की संख्या में 61.3% योगदान दिया। केंद्रीय संरक्षित टिकटवाले स्मारकों में देशी पर्यटकों के लिए 2016 में सबसे ज्यादा पर्यटकों द्वारा देखा गया स्मारक ताजमहल था, उसके बाद कुतुब मीनार तथा लाल किला का नंबर आता है। इसी प्रकार विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे ज्यादा पर्यटन स्मारक ताजमहल था। इसके बाद आगरा फोर्ट तथा कुतुब मीनार का नंबर आता है।

9.18 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। हाल ही में उठाए गए कदमों में 163 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटकों, मेडिकल एवं बिजिनेस की तीन श्रेणियों के अंतर्गत ई-वीसा की सुविधा शुरू की गई विभिन्न चैनलों पर 2017-18 के लिए ग्लोबल मीडिया अभियान की शुरूआत, भारत में विश्व धरोहर स्थलों को लोकप्रिय बनाने के लिए ''दि हेरिटेज ट्रेल''; भारतीयों को अपने देश के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से ''देखो अपना देश'' नाम से 3 घटकों वाले ''पर्यटन पर्व'' का अनुष्ठान, देश के सभी राज्यों के स्थल विशेष में पर्यटन समारोह ''पर्यटन, सभी के लिए'' का आयोजन; और विभिन्न मसलों पर पणधारकों के साथ ''पर्यटन एवं शासन'' पर संवाद पत्र एवं कार्यशाला का आयोजन इत्यादि। ई-पर्यटक वीसा के जरिए विदेशी पर्यटकों की संख्या में 143 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह 2016 के 10.8 लाख से बढ़कर 2017 के दौरान 17.0 लाख हो गई। इसमें 57.2 प्रतिशत तक बढ़त हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी-बीपीएम सेवाएं

9.19 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी-बीपीएम में 8.1% की दर से वृद्धि हुई और नासकॉम के आंकड़ों के अनुसार 2015-16 में 129.4 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2016-17 में 139.9 बिलियन अमरीकी डालर (ई-कामर्स तथा हार्डवेयर को छोड़कर) हो गया। आईटी-बीपीएम निर्यातों में 7.6% वृद्धि हुई और इसी अवधि के दौरान यह 107.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 116.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। 2016-17 में ई-कामर्स बाजार में 19.1% वृद्धि दर के साथ व्यापार तकरीबन 33 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है। बहरहाल, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, साफ्टवेयर निर्यातों में वर्ष 2016-17 में (-) 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। 2017-18 की पहली छमाही में इसमें 2.3% का इज़ाफा हुआ। अमरीका, इग्लैंड और यूरोपियन यूनियन देशों का आईटी-आईटीईएस निर्यातों में तकरीबन 90% योगदान है। यद्यपि इन पारंपरिक देशों में नई चुनौतियां उभर कर आ रही है, एपैक, लेटिन अमरीका, और मिडिल ईस्ट एशियाई देशों से मांग बढ़ रही है और यूरोप महाद्वीप, जापान, चीन और अफ्रीका में विस्तारण के लिए अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

9.20 कुल मिलाकर 2016-17 में आईटी-बीपीएम उद्योग में तकरीबन 3.9 मिलियन लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है, जोकि 2015-16 की तुलना में 173,000 व्यक्ति अधिक हैं। इस उद्योग-जगत में 16,000 से अधिक फर्में है, जो 4,750 स्टार्ट-अप्स सहित संपूर्ण सेवाएं मुहैया करती हैं। दशक (2006-2016 के दौरान) भारत के कुल सेवा निर्यातों में आईसीटी के हिस्से में कुछ गिरावट आई है, जबकि चीन, ब्राजील, रूस, फिलीपीन्स, इज़राइल और यूक्रेन जैसे देशों में कुल सेवा निर्यातों में आईसीटी के हिस्से में वृद्धि हुई है, जोकि भारत के लिए इन देशों से टक्कर की प्रतिस्पर्धा दर्शाता है (चित्र: 6)।

9.21 इस सेक्टर को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें डिजिटल समावेशन सृजित करने में सहायता करना, समतापूर्ण वृद्धि हासिल करना और 1.45 लाख व्यक्तियों को रोज़गार मुहैया कराने के लिए, ज्यादातर छोटे शहरों में बीपीओ संवर्धन एवं साझा सेवा केन्द्रों को स्थापित करना; 5000 सीटों वाली पृथक पूर्वोत्तर बीपीओ संवर्धन योजना, जिसके तहत 15,000 व्यक्तियों को रोज़गार मिल सकता है, की स्थापना, खुली डाटा संरक्षण नीति कानून के प्रारूप को तैयार करने के अलावा, दीर्घ कालिक शुरूआतें जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी ई-गवर्नेंस, कौशल भारत के जरिए डिजिटल प्रतिभा को प्रोत्साहन, नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर पलायन और स्टार्ट-अप इंडिया के जरिए अभिनव परिवर्तन को जागृत करने के प्रयास आदि शामिल हैं।

स्थावर संपदा और आवासन

9.22 स्थावर संपदा क्षेत्र का हिस्सा, जिसमें मकानों का स्वामित्व भी शामिल है, 2015-16 में भारत की समग्र जीवीए का 7.7 प्रतिशत था। पिछले तीन वर्षों में इस क्षेत्र की वृद्धि में कमी आई है, जोकि 2013-14 में 7.5 प्रतिशत से कम हो कर 2014-15 में 6.6 प्रतिशत हो गई और यह 2015-16 में और घटकर 4.4 प्रतिशत हो गई। ऐसा मुख्यत: रिहायशी क्षेत्र के स्वामित्व में वृद्धि के कारण हुआ जोकि समग्र जीवीए का 6.8 प्रतिशत था, जो 2013-14 में 7.1 प्रतिशत घटकर 2015-16 में 3.2 प्रतिशत हो गया। निर्माण क्षेत्र, जिसमें इमारतें, बांध, सड़क, पुल इत्यादि शामिल हैं, की वृद्धि में कमी आई, जो 2015-16 में 5.0 प्रतिशत से कम होकर 2016-17 में 1.7 प्रतिशत रह गई।

9.23 2017 के पहली छमाही के दौरान 14 प्रमुख शहरों में आवासीय योजनाओं की संख्या पिछले पांच वर्षों में न्यूनतम रही, जो राष्ट्रीय स्थावर संपदा विकास परिषद के अनुसार 58,000 इकाई थी। इसी तरह नए मकानों की बिक्री भी इसी अवधि के दौरान 5 वर्षों में न्यूनतम रही, जोकि लगभग 101,850 इकाई थी। यद्यपि 2016 की पहली छमाही की तुलना में 2017 की पहली छमाही में बिक्री में 38 प्रतिशत

चित्र 6: आईसीटी सेवा निर्यात (सेवा निर्यात का प्रतिशत, बीओपी)

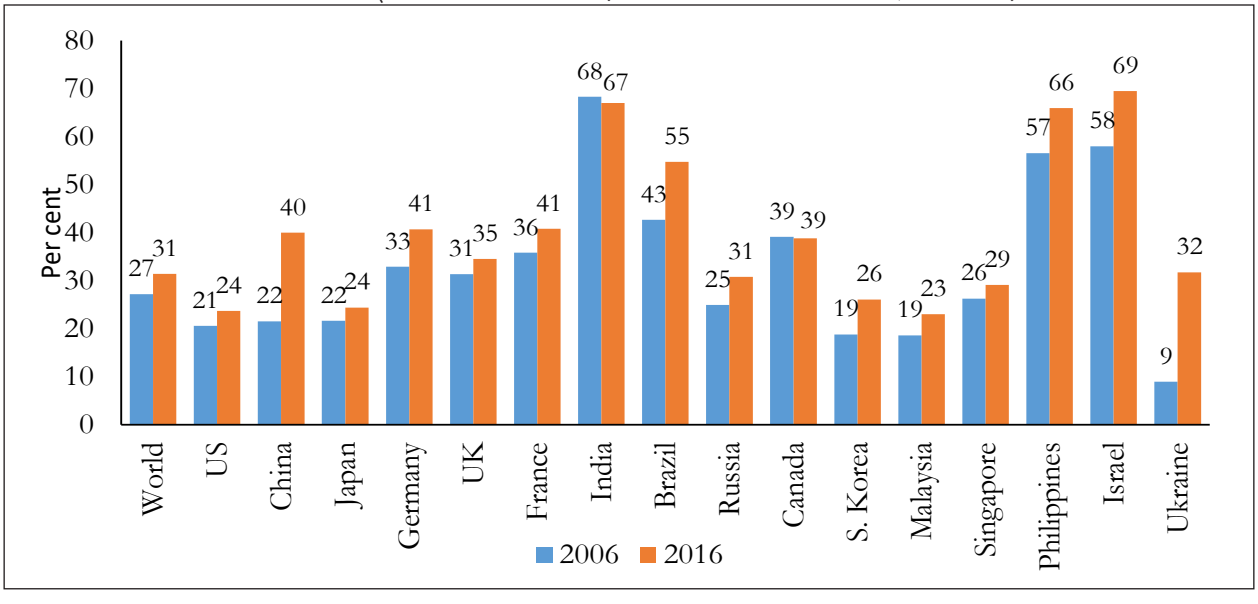

स्रोत: विश्व बैंक डाटा

टिप्पणी: आईसीटी-सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवा निर्यातों में कम्प्यूटर और संचार सेवाएं (दूरसंचार और डाक और कोरियर सेवाएं) और सूचना संबंधी सेवाएं शमिल हैं (कम्प्यूटर डाटा और समाचार संबंधी सेवाओं के लेन-देन)

कमी आई, इसी अवधि के दौरान नई इकाइयों को शुरू करने में 56 प्रतिशत कमी आई। यद्यपि कुछ हाल के सुधारों से भले ही कुछ समय के लिए आवासीय बाजारों पर प्रभाव पड़ा हो इन सुधारों से अनबिक मांग सूची स्तर जो अप्रैल, 2016 में 888,373 थी में कमी होकर अक्तूबर, 2017 में 807,903 यूनिट रह गई। स्थावर संपदा क्षेत्र में निजी इक्विटी के निवेश में भागीदारी 2013 में 0.9 बिलियन अमरीकी डालर बढकर 2016 में 5.9 बिलियन डालर थी जो इस अवधि के दौरान छह गुणा से अधिक दर्ज की गई। 2016 में 5.9 प्रतिशत बिलियन डॉलर थी जोकि इस अवधि के दौरान 5 गुणा वृद्धि दर्शाता है। भारतीय स्थावर संपदा में वर्ष 2017 में पिछले एक दशक की तुलना में उच्चतम सालाना निवेश होने की संभावना है और लगभग 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की धनराशि जनवरी से जून 2017 के बीच निवेशित की जा चुकी है। सशक्त भारतीय अर्थव्यवस्था और कई वृद्धि समर्पित सुधारों को आरंभ करने के साथ जनसंख्या में वृद्धि इत्यादि स्थावर संपदा क्षेत्र में उच्चतर निवेश आकर्षित हो रहा है। 2016 की शुरूआत से भारतीय स्थावर संपदा ने 10.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक धनराशि का संस्थागत निवेश (वाणिज्यिक स्थावर संपदा को छोड़कर) आकर्षित किया है, जोकि 2013 से कुल निवेश का आधा है, या इससे अधिक ही है। निर्माण विकास क्षेत्र में एफडीआई पांच वर्ष में सबसे कम होकर वर्ष 2016 में 107 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया था। पांच वर्षों में एफडीआई निवेश में उल्लेखनीय और सतत कमी का कारण यह था कि अपतट निवेशक अपनी अधि कतर निधियाँ ऋण या स्तरित ऋण के माध्यम से निवेश कर रहे थे। विकासकर्ताओं को दिए ऋण पर निश्चित प्रतिफल देने के कारण उनके निवेशों की रक्षा होती है और साथ ही निवेशों का खतरा कम हो जाता है। तथापि इसमें सुधार के लक्षण आने लगे हैं उसी वर्ष 2017 की पहली छमाही में 257 मिलियन अमेरिकी डालर का कुल एफडीआई और वर्ष 2016 के पूरे वर्ष के कुल एफडीआई के दोगुने से अधिक है। कुल सकारात्मक भावना का श्रेय अनेक कारकों, जैसे विनियामक माहौल, अवसंरचना में वृद्धि और स्थावर संपदा निवेश न्यासों (आरईआईटी) को दिया गया था। इन नीतिगत पहलों से अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही आने तथा सेक्टर को बेहतर ढंग से संगठित और स्तरित करने और उसके जरिए निवेश बढ़ाने की संभावना है। मांग पक्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) के अलग-अलग आवास ऋण वितरण में 2015-16 की तुलना में 2016-17 में लगभग 11 प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि, पीएसबी और एचएफसी के अलग-अलग आवासीय गृह ऋण विभागों की बढ़ती गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां चिंता का विषय है।

9.24 एनएचबी रेजीडेक्स के अनुसार अप्रैल-जून 2017 के दौरान 50 प्रमुख शहरों में से 36 शहरों में गृह मूल्य सूचकांक में बढ़ती वार्षिक प्रवृत्ति देखने को मिली हैं। इनमें विशाखापट्टनम की वृद्धि सबसे अधिक 15.7 प्रतिशत, दिल्ली की 8.1 प्रतिशत और नोएडा की वृद्धि सबसे कम 0.9 प्रतिशत थी। सूचकांक में कमी दर्शाने वाले 13 शहरों में सबसे अधिक कमी भिवाड़ी (-10.6 प्रतिशत) में देखी गई, इसके बाद कोयम्बतूर (-6.6 प्रतिशत) और चंडीगढ़ (-5.9) प्रतिशत का स्थान रहा।

9.25 गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए) के बढ़ने, स्थावर संपदा सेक्टर को जोखिमपूर्ण बताने और स्थावर संपदा सेक्टर में लाभ कम होने से बैंक इस सेक्टर को ऋण देने के प्रति अनिच्छुक हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप स्थावर संपदा को संगठित निधीयन में वर्ष 2013 में 68 प्रतिशत की कमी की तुलना में वर्ष 2016 में 17 प्रतिशत की कमी आई है। रोचक बात यह है कि प्राइवेट इक्विटी (पीई) निधियों और वित्तीय संस्थाओं जैसे पेंशन निधियों और संप्रभु धन निधियों ने इस सेक्टर के सबसे बड़े स्रोत के रूप में बैंकों का स्थान ले लिया है। स्थावर संपदा के क्षेत्र में निजी सम्पदा (पीई) निधियों और इन संस्थाओं का अंश वर्ष 2013 में 14 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016 में 82 प्रतिशत से अधिक हो गया है। 2013-16 की अवधि के लिए संचयी आधार पर पीई निधियां, निधियन की सबसे बड़ी स्रोत रही हैं जिनकी हिस्सेदारी (शेयर) 57 प्रतिशत थी, इसके बाद बैंकों की ऋण देनदारी थी जो 34 प्रतिशत थी। जबकि शेष 9 प्रतिशत का निधियन एफडीआई से आने वाले धन से किया जाता है।

9.26 स्थावर संपदा और निर्माण दोनों मिल कर देश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इस क्षेत्र ने वर्ष 2013 में 40 मिलियन जनशक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाया और अनुमानों के अनुसार वर्ष 2017 तक लगभग 52 मिलियन और वर्ष 2022 तक लगभग 67 मिलियन जनशक्ति को इस क्षेत्र द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाने की आशा है। इससे स्पष्ट है कि अगले 5 वर्षों में यह क्षेत्र 15 मिलियन से अधिक रोजगार पैदा करेगा, जो प्रति वर्ष तीन मिलियन रोजगार के रूप में परिवर्तित होगा।

स्थावर संपदा और निर्माण क्षेत्र में नियोजित लगभग 90 प्रतिशत जनशक्ति भवनों के निर्माण कार्य में संलग्न है। शेष 10 प्रतिशत जनशक्ति निर्माण कार्य को पूरा करने, अंतिम रूप देने, वैद्युत, प्लंबिंग, अन्य संस्थापन सेवाओं, विध्वंस (तोड़-फोड़) और स्थल को तैयार करने जैसे कार्यों में संलग्न रहती है। स्थावर संपदा और निर्माण क्षेत्र में लगभग 80 प्रतिशत रोजगार अल्प कुशल जनशक्ति के लिए होते हैं जबकि कुशल जनशक्ति का अंश 9 प्रतिशत होता है और शेष क्लर्क, तकनीशियन और इंजीनियर वर्गों तक फैला हुआ है। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) के अनुसार वर्ष 2022 तक स्थावर संपदा और निर्माण क्षेत्र के लिए लगभग 66 मिलियन लोगों की जरूरत होगी जो सभी क्षेत्रों (सेक्टरों) में सबसे बड़ा है।

9.27 स्थावर संपदा क्षेत्र में कुछ हालिया सुधारों और नी. तियों में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शामिल है जिसमें सरकार ने नवंबर, 2017 तक शहरी क्षेत्रें में वहनीय आवासीय खंड के लिए 3.1 मिलियन आवासीय इकाइयों को मंजूरी दी है इनमें से, 1.6 मिलियन आवासों का नीवं खड़े किए गए हैं और निर्माण के विभिन्न चरण पर हैं और इस मिशन के अंतर्गत लगभग 0.4 मिलियन आवासों का निर्माण किए गए हैं। वहनीय आवासीय खंडों के लिए 21 सितंबर, 2017 को पीपीपी नीति भी घोषित की गई थी ताकि ''वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास'' नामक महात्वाकांक्षी मिशन को और बल दिया जा सके। पीएमएवाई के अंतर्गत उधार से जुड़ी सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) मध्यम आय वर्ग (एमआईपी) खंड तक विस्तारित की गई जिसे 1 जनवरी, 2017 से स्कीम में शामिल किया गया। स्थावर संपदा (वि. नियमन और विकास) अधिनियम, 2016 का अधिनियमन हो जाने पर अनुमान है कि जवाबदेही से स्थावर संपदा मूल्य श्रृंखला में उच्च वृद्धि होगी जबकि अनिवार्य प्रकटनों और पंजीकरणों से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

अनुसंधान और विकास

9.28 सीएसओ की नई पद्धति के अनुसार, अनुसंधान और विकास (आर ऐंड डी) के लिए अलग से शीर्ष नहीं है जो व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों का भाग होता है। इन सेवाओं में क्रमशः 2014-15 और 2015-16 में 17.5 प्रतिशत और 41.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत स्थित आरएंडडी सेवा कंपनियों में लगभग 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो वैश्विक बाजार का 22 प्रतिशत है। तथापि, अनुसंधान और विकास पर भारत का सकल व्यय काफी कम अर्थात सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1 प्रतिशत रहा है। वर्तमान में वैश्विक नवाचारी सूचकांक (जीआईआई) 2017 में भारत का रैंक 127 में से 60वां है, हालांकि वर्ष 2016 में 66वां रैंक से इसमें सुधार हुआ है। ब्रिक्स देशों में केवल दक्षिण अफ्रीका ही अनुसंधान और विकास व्यय रैंक में भारत से पीछे है।

सारणी 6: कुछ चुनिंदा कंपनियों का वैश्विक नवाचारी सूचकांक

	वैश्विक नवचारी		मानव पूंजी और अनुसंधान		अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)		अनुसंधानकर्ता		अनुसंधान और विकास	
देश	(रैंक)	(स्कोर)	(रैंक)	(स्कोर)	(रैंक)	(स्कोर)	(रैंक)	(स्कोर)	(रैंक)	(स्कोर)
ब्राजील	69	33.1	50	35.9	29	37.2	55	8.3	32	26.9
चीन	22	52.5	25	49.2	17	58.5	45	14.1	17	48.5
भारत	**60**	**35.5**	**64**	**32.3**	**32**	**35.9**	**81**	**1.8**	**43**	**19.1**
दक्षिण कोरिया	11	57.7	2	66.2	1	88.2	3	85.8	2	98.4
रूस	45	38.8	23	50	25	41.5	29	37.8	34	26.1
दक्षिण अफ्रीका	57	35.8	60	32.8	39	27.1	65	5.2	48	16.6
यूनाइटेड किंगडम	5	60.9	6	63.3	10	69.5	18	54.1	21	39.5
संयुकत राज्य अमेरिका	4	61.4	13	57.2	4	78.8	20	51.2	10	65

स्रोत: वैश्विक नवचारी सूचकांक, 2017

9.29 वर्ष 2016 के लिए इंजीनियरी अनुसंधान और विकास खंड में सेवा प्रदाताओं की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार विश्व भर में अनुसंधान और विकास पर खर्च करने वाले 500 शीर्षस्थ लोगों द्वारा अनुसंधान और विकास पर खर्च में पिछले दो वर्षों की तुलना में लगातार 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिनमें डिजिटल दृष्टि से प्रथम अनुसंधान और विकास संगठन बनाने पर बल रहा है। वर्ष 2016 में कुल अनुसंधान और विकास वैश्वीकरण और सेवा अवसरों का 232 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान था और वर्ष 2021 तक इसके 289 बिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान है। अंतस्थापित (इम्बेडेड) और साफ्टवेअर इंजीनियरी अनुसंधान और विकास आउटसोर्सिंग बाजार का 76 प्रतिशत होता है। भौगोलिक विस्तार में भारत, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका का 75 प्रतिशत, वैश्विक इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास सेवा बाजार पर कब्जा है। भारत का इंजीनियर अनुसंधान और विकास (ईआर एंड डी) वैश्वीकरण और सेवा बाजार, जो वर्तमान में 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, उनके 2020 तक 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो जाने की आशा है।

9.30 तथापि, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार भारत की नवाचार क्षमता, अमेरिका यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया की नवाचार क्षमता से कम है परंतु चीन की क्षमता से अधिक है। अनुसंधान और विकास पर विश्वविद्यालय-उद्योग सहयोग की दृष्टि से भारत की रैंक सभी ब्रिक्स देशों से बेहतर है और वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों की उपलब्धता की दृष्टि से यह चीन को छोड़कर अन्य ब्रिक्स देशों से बेहतर स्थिति में है। तथापि प्रति-मिलियन जनसंख्या पर पेटेंट के आवेदनों की दृष्टि से भारत अन्य ब्रिक्स देशों से काफी पीछे है और अनुसंधान और विकास पर कंपनी के व्यय की दृष्टि से भारत चीन से कुछ नीचे है (सारणी 7)

9.31 सरकार ने भारत में अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) क्षेत्र के विकास के लिए अनेक पहलें की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत रूपांतरण राष्ट्रीय संस्थान (नीति) आयोग में अटल नवाचारी मिशन (एआईएम) स्थापित करना शामिल है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 में भारत और इजरायल के बीच करार में अगले दो वर्षों में प्रत्येक पक्ष से 01 मिलियन अमेरिकी डालर का प्रावधान है, ताकि स्वास्थ्य देखभाल और साइबर सुरक्षा में बड़े पैमाने पर आंकड़ा विश्लेषण के क्षेत्र में नई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता दी जा सके। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम ओ ईएफसीसी) ने वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले हाइड्रोफ्लूरोकार्बन्स (एचएफसी) जैसी प्रशीतक गैसों के विकल्प के रूप में अगली पीढ़ी की दीर्घकालिक प्रशीतक प्रौद्योगिकियां विकसित करने के

सारणी 7: वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक: अनुसंधान और विकास नवाचार

देश समग्र नवाचार	नवाचार की क्षमता		वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं की गुणवत्ता		अनुसंधान और विकास पर कंपनी का खर्च		आर ऐंड डी के क्षेत्र में विश्वविद्यालय उद्योग सहयोग		वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धता		प्रदत्त पीटीसी पेटेंट/मिलियन जनसंख्या			
	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक
संयुक्त रजाज्य अमेरिका	6.0	2	6.0	5	5.9	2	5.7	2	5.7	2	176.5	10	5.8	2
यूनाइटेड किंगडम	5.5	11	6.3	2	5.1	14	5.4	6	4.9	17	99.1	18	5.1	12
दक्षिण कोरिया	4.7	35	4.8	32	4.4	28	4.4	27	4.5	38	249.5	5	4.8	18
भारत	**4.5**	**42**	**4.7**	**35**	**4.5**	**23**	**4.4**	**26**	**4.6**	**32**	**1.7**	**63**	**4.1**	**29**
चीन	4.5	44	4.6	36	4.6	21	4.4	28	4.7	29	17.7	30	4.1	28
दक्षिण अफ्रीका	4.9	30	4.4	42	4.3	32	4.4	29	3.5	100	5.8	49	3.8	39
रूस	4.2	65	4.4	41	3.5	54	3.9	42	4.3	50	7.8	46	3.5	49
ब्राजील	4.1	73	3.7	77	3.4	62	3.4	70	3.6	90	3.4	53	3.2	85

स्रोत: वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2017-18, वैश्विक आर्थिक मंच
टिप्पणी: पीसीटी-पेटेंट सहयोग संधि

लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पहल की है ताकि ओजोन की परत और जलवायु पर इसके प्रभाव को कम किया जा सके। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का उद्देश्य लंबित बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के आवेदनों को अनुमति देने में लगने वाले समय को कम करना है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान (डीएमआ. ईआर), कारपोरेट उद्योग द्वारा स्थापित आंतरिक अनुसंधान और विकास यूनिटों जैसी नई प्रोद्योगिकियों डिजाइन और इंजीनियरी का विकास, प्रक्रिया/उत्पाद/डिजाइन सुधार, विश्लेषण और परीक्षण की नई पद्धतियां विकसित करने, पूंजी उपस्कर, सामग्री और ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण, बहि:स्राव शोधन, कचरे के पुन:चक्रण आदि को मान्यता प्रदान करने/ पंजीकृत करने की एक स्कीम चला रहा है। 31 दिसंबर, 2016 तक की स्थिति के अनुसार डीएसआईआर द्वारा 1900 फर्मों की आंतरिक आर एंड इकाइयों को मान्यता प्रदान की गई। इनमें से लगभग 60 कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, स्वास्थ्य देखभाल, विद्युत, इंजीनियरी, जैव प्रौद्यो. गिकी, रक्षा आदि के क्षत्र में अनुसंधान और विकास सेवाएं प्रदान कर रही है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् डीएसआईआर की एक स्वायत्त निकाय है, जो विभिन्न विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में इसके आधुनिक अनुसंधान और विकास संबंधी ज्ञान आधार के लिए जाना जाता है और अपनी 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से पैन इंडिया की उपस्थिति देता है जोकि मूल और प्रयोगिक अनुसंधान पर केंद्रित है। सीएसआईआर ने 39 आउटरीच केंद्रों और 3 नवोन्मेष परिसरों की भी स्थापना की है। सीएसआईआर की अनुसंधान और विकास संबंधी विशेषज्ञता और अनुभव लगभग 3700 सक्रिय वैज्ञानिकों में निहित है जिन्हें लगभग 6000 वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों द्वारा सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) जो डीएसआईआर का लोक क्षेत्र उद्यम है प्रौद्योगिकियों के लाइसेंसिंग और उद्योगों को जानकारी देने हेतु समग्र तकनीकी अंतरण सेवाएं प्रदान करता है। यह कार्य अनुसंधान व विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि द्वारा एनआरडीसी को सौंपे जाते हैं।

9.32 सरकार की सहायता से मिले बल से भारत में अनुसंधान और विकास क्षेत्र में आगामी वर्षों में जबर्दस्त वृद्धि रही है। प्रबंधन परामर्शी फर्म जिनोव द्वारा एक अध्ययन के अनुसार, भारत में इंजिनियरिंग आर एण्ड डी बाजार के 14 प्रतिशत की चक्रवर्धी दर से बढ़ने का अनुमान है जोकि 2020 तक 42 बिलियन अमरीकी डालर पहुंच जाएगा। भारत कृषि और भेषजीय क्षेत्र में मजबूत वृद्धि होने का भी अनुमान है क्योंकि सरकार इन क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास हेतु समर्पित अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करने के लिए बड़ी राशि निवेश कर रही है। भारतीय आईटी उद्योग के भी आर एण्ड डी क्षेत्र के विकास में योगदान करने की उम्मीद है।

अंतरिक्ष सेवाएं

9.33 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जिसमें सामाजिक विकास और कार्यनीतिक अपेक्षाओं से संबंधित मुद्दों का निराकरण करने के लिए संचार, नौसंचालन तथा भू-प्रक्षेपण शामिल हैं, की अनुप्रयोज्यता के जरिए राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है। उपग्रह मानचित्रण और प्रक्षेपण सेवाएं ऐसे दो क्षेत्र है जहां भारत अपनी धाक जमा रहा है-ये क्षेत्र भविष्य में बहुत संभावनाओं से भरे हुए भी हैं। उपग्रह मानचित्रण में, हालिया वर्षों में विदेशी मुद्रा अर्जन में गिरावट आई है, यह मुख्यतया कई उपग्रह एजेंसियों द्व ारा अपनाई गई नि:शुल्क और खुली डाटा नीति के कारण रहा है। भारत संविदाओं के नवीकरण के लिए उपभोक्ताओं के साथ बातचीत कर रहा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) भारतीय रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स (रिसोर्ससेट-2 और ओशियन सेट-2 से) आंकड़े प्राप्त करने और उन्हें संसाधित करने के लिए म्यांमार सहित आसियान सदस्यों को सहायता प्रदान करने और आसियान सदस्य देशों के लाभार्थ अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोज्यताओं में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी एक परियोजना को चला रहा है। एंट्रिक्स, फिलहाल, इंडियन रिमोट सेंसिंग (आईआरएस) उपग्रहों से सीधे संकेत प्राप्त करने और डाटा के प्रोसेसिंग को समर्थ बनाता है खासकर अंतरराष्ट्रीय ग्राउंड स्टेशनों/भारत के बाहर प्रोसेसिंग सुविधाओं पर रिसोर्स सैट-2, ओसन सेट-2 और कार्टो सैट-II निर्यात हेतु काफी संभावना है और एंट्रिक्स, अंतरराष्ट्रीय ग्राउंड स्टेशन (आईजीएस) को बढ़ाने पर कार्य कर रही है और इस संबंध में वार्ताएं अगले चरण पर है। वर्ष 2017-18 के दौरान, एंट्रिक्स, आईआरएस डाटा के वितरण हेतु पूरे विश्व में विभिन्न विक्रेताओं के साथ कार्य कर रहा है जिसमें यूरोप, यूएसए, लैटिन अमरीका, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्वी देश शामिल हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, इन प्रयासों को मजबूत किया जा सकेगा। इसरो द्वारा जारी नए उत्पादों और सेवाओं को एंट्रिक्स द्वारा विपणन किया जा सकेगा।

9.34 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, उपग्रह प्रेक्षण के क्षेत्र में, पीएसएलवी ने 254 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिए हैं। इनमें 37 राष्ट्रीय उपग्रह, विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक

संस्थानों द्वारा निर्मित 8 विद्यार्थी उपग्रह, एक पुनः प्रविष्टि मिशन और 29 देशों के 209 विदेशी उपग्रह शामिल हैं। उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के निर्यात से भारत के विदेशी मुद्रा अर्जन में 2014–15 में 149 करोड़ रुपए से 2015–16 और 2016–17 में 394 करोड़ रुपए और 275 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण सेवा राजस्व में भारत की हिस्सेदारी 2014–15 में 0.3 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 में 1.1 प्रतिशत हो गई। 2015–16 में विदेशी मुद्रा अर्जन, अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए दो समर्पित ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) के कारण अधिक रहा, जबकि 2016–17 में, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह मिशनों के लिए सह-यात्रियों के रूप में केवल अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। एंट्रिक्स को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अपनी निचली पृथ्वी कक्ष (एलईओ) उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी-एमके III प्रक्षेपण सेवाओं के काफी अधिक उपयोग की संभावनाएं दिखाई देती हैं।

निष्कर्ष

9.35 भारत का सेवा क्षेत्र वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2017–18 में बढ़ने की संभावना है। यह सुधार निक्की/आईएचएस मार्किट सेवा क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में भी प्रतिबिम्बित होता है जो नवम्बर, 2017 में 48.5 रहा लेकिन दिसम्बर, 2017 में यह सुधर कर 50.9 हो गया। पयर्टन, विमानन और दूरसंचार जैसे उप क्षेत्रों में बेहतर निष्पादन के साथ उज्ज्वल संभावनाएं दिखाई देती हैं। सेवा कारोबार के बेहतरीन निष्पादन से सॉफ्टवेयर जैसी प्रमुख सेवाओं का विकास भी सकारात्मक रूख पर है। तथापि, सॉफ्टवेयर और कारोबारी सेवाओं के लिए वैदेशिक माहौल में ह्रास का जोखिम बना रहता है।